

वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति

प्रलिस के लिये:

वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति, [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#), सेंसरशिप व्यवस्था, [भारतीय दंड संहिता](#), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, [केंद्रीय फिलिम प्रमाणन ब्यूरो \(CBFC\)](#), [सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता\) नयिम, 2021](#)

मेन्स के लिये:

वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति, भारत में सेंसरशिप व्यवस्था और इसके लाभ तथा सीमाएँ, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ एवं क्षमता, पारदर्शिता व जवाबदेही

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

फ्रीडम हाउस (वाशिंगटन DC स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था) द्वारा वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, **पछिले 13 वर्षों से इंटरनेट की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट** की एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें 29 देशों में मानवाधिकारों के लिये ऑनलाइन पारस्थितिकी तंत्र की स्थिति गंभीर पाई गई है।

- इस रिपोर्ट में जून 2022 और मई 2023 के बीच इंटरनेट की स्वतंत्रता के संदर्भ में हुए विकास को कवर किया गया है। यह विश्व भर के 88% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की हसिसेदारी रखने वाले **70 देशों** में इंटरनेट की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करती है।
- यह रिपोर्ट देशों का मूल्यांकन करने के लिये **पाँच सेंसरशिप तरीकों** का उपयोग करती है, जिसमें **इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रतबंध, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतबंध, वेबसाइट ब्लॉक, VPN ब्लॉक और सामग्री (कंटेंट) को इंटरनेट से जबरन हटाया जाना** शामिल है।

रिपोर्ट के प्रमुख बडि:

- डिजिटल नयितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका:**
 - डिजिटल नयितरण में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। तेज़ी से परष्कृत और सुलभ होते जा रहे **AI-आधारित उपकरणों** का उपयोग कम-से-कम **16 देशों** में गलत सूचना को प्रसारित करने के लिये किया जा रहा है।
 - इसके अतरिकित राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक कारणों से अनुपयुक्त मानी जाने वाली **सामग्री/कंटेंट** को स्वचालित रूप से हटाकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता **22 देशों** में सेंसरशिप दक्षता व प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
- ऑनलाइन अभवियक्ता के कानूनी परणाम और हसिक घटनाएँ:**
 - मूल्यांकन में शामिल 70 देशों में से रकिर्ड 55 देशों में उपयोगकर्ताओं को **ऑनलाइन अभवियक्ता के कानूनी परमाण** भुगतने पड़े।
 - इसके अतरिकित **41 देशों में व्यक्तियों पर उनके ऑनलाइन बयानों के कारण हमला किया गया या फरि उनकी हत्या कर दी गई।**
- राष्ट्र-वशिषिट नषिकर्ष:**
 - ईरान में इंटरनेट शटडाउन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की ब्लॉकगि एवं सरकार वरिधी प्रदर्शनों को दबाने के लिये नगिरानी व्यवस्था को और ठोस किया जाना आदि **डिजिटल व इंटरनेट नयितरण में काफी वृद्धिको दर्शाता है।**
 - इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में चीन का प्रदर्शन लगातार नौवें वर्ष सबसे खराब रहा, इसके बाद ऑनलाइन स्वतंत्रता के मामले में म्याँमार दूसरा सबसे दमनकारी देश रहा।**
- भारत में AI-आधारित सेंसरशिप:**
 - भारत अपने **कानूनी ढाँचे में AI-आधारित सेंसरशिप** का उपयोग कर रहा है, जिससे अभवियक्ता की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है और **सत्तारूढ दल की आलोचना** करना कठिन हो गया है।
 - इस रिपोर्ट में **सेंसरशिप व्यवस्था में वसितार** के कारण भारतीय लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर चेतावनी दी गई है, जिससे देश में आगामी वर्ष 2024 में पारदर्शी और नषिपक्ष आम चुनाव हो पाना भी एक चुनौती हो सकती है।

संसरशपि:

- संसरशपि ऐसी जानकारी, सूचनाओं, वचिारों अथवा अभवियक्तियों को दबाने अथवा नयित्तरति करने का कार्य है जो कसिी वशिष समूह, संगठन या सरकार के लयि आपत्तजिनक, हानकारक, संवेदनशील माना जाता है ।
- इसके अंतरगत वयक्तियों, संस्थानों अथवा अधकारियों द्वारा कुछ कंटेंट के प्रसार, प्रकाशन या इन तक पहुँच को प्रतबिंधति अथवा सीमति करना शामिल है ।
- भारत के संसरशपि नयिओं के दायरे में सभी प्रकार की कला, नृत्य, साहित्य, लखिति, वृत्तचतिर और मौखकि कार्यों के साथ-साथ वजिापन, थिएटर, फलिमें, टेलीवजिन शो, संगीत, भाषण, रपिरट एवं बहस शामिल है ।

भारत में संसरशपि की कार्यप्रणाली:

- **दंड प्रकरया संहति (Cr.P.C):**
 - Cr.P.C की धारा 95 कुछ कंटेंट/प्रकाशनों को ज़ब्त करने का प्रावधान करती है ।
 - यद कसिी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज़, चाहे वह कहीं भी मुद्रति हो, में ऐसी कोई जानकारी शामिल है जसै राज्य सरकार राज्य के लयि हानकारक मानती है, तो इस प्रावधान के तहत जारी एक आधकारकि अधसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उसे दंडति कया जाता है ।
- **केंद्रीय फलिम प्रमाणन ब्यूरो (Central Bureau of Film Certification- CBFC):**
 - **केंद्रीय फलिम प्रमाणन ब्यूरो सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952** के तहत संचालति एक वैधानकि नकिया है ।
 - यह सार्वजनकि डोमेन के फलिमों की सामग्री के वनियमन का कार्य करता है ।
 - फलिमें CBFC द्वारा पूव प्रमाणन के अधीन होती हैं तथा प्रसारकों को **"प्रोग्राम कोड और वजिापन कोड"** नयिओं द्वारा प्रमाणन की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है ।
- **भारतीय प्रेस परबिद:**
 - यह **प्रेस काउंसलि अधनियम, 1978** के तहत स्थापति एक वैधानकि और अरद्ध-नयायकि नकिया है ।
 - यह प्रेस के लयि स्व-नयिमक नकिया के रूप में कार्य करती है और मीडया डोमेन में आने वाली चीज़ों को वनियमति करती है ।
 - यह मीडया कर्मयिों और पत्रकारों के लयि स्व-नयिमन का अभ्यास करने की आवश्यकता पर ज़ोर देने के साथ ही सामान्य रूप से मीडया सामग्री पर नगिरानी रखने का कार्य करती है ताकि यह नरिधारति कया जा सके कि प्रकाशति-प्रसारति कंटेंट प्रेस की नैतिकता और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप है अथवा नहीं ।
- **केबल टेलीवजिन नेटवर्क अधनियम, 1995:**
 - यह अधनियम प्रसारति कया जा सकने वाली सामग्रीयों को वनियमति करता है ।
 - यह अधनियम केबल ऑपरेटरों का अनुवीक्षण करता है, इस अधनियम के तहत केबल ऑपरेटरों के लयि पंजीकरण कराना अनवार्य है ।
- **सोशल मीडया प्लेटफॉर्म और नए सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021:**
 - सोशल मीडया के वसितार को देखते हुए भारत में इसकी संसरशपि चति का वषिय रहा है कयोंकि हाल में कुछ समय पहले तक यह क्षेत्र कसिी भी सरकारी प्राधकिरण की प्रत्यक्ष नगिरानी अथवा प्रत्यक्ष और वशिषि वनियमन के अधीन नहीं था ।
 - वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 सोशल मीडया के उपयोग को वनियमति करता है । इसके तहत वशिष रूप से धारा 67A, 67B, 67C तथा 69A में वशिषि नयिमक खंड शामिल हैं ।
- **IT (मध्यवर्ती वशि-नरिदेश और डजिटिल मीडया आचार संहति) नयिम, 2021:**
 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B), भारत सरकार के दायरे में फलिमों, ऑडयो-वजिअल कार्यकरमों, समाचारों, समसामयकि मामलों के कंटेंट और अमेज़न, नेटफ्लक्स तथा हॉटस्टार जैसे **OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्मों** सहति डजिटिल व ऑनलाइन मीडया को लाने के लयि भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 के तहत **"व्यावसायकि आवंटन नयिमों"** में बदलाव कया है ।

संसरशपि के लाभ और सीमाएँ:

- **लाभ:**
 - **सामाजकि सद्भाव को बनाए रखने में संसरशपि की भूमकि:** संसरशपि समाज में असामंजस्य को बढ़ावा देने वाले तथा सांप्रदायकि वविदों को जन्म देने वाले आपत्तजिनक सामग्रीयों के प्रकटीकरण अथवा प्रसार को रोकने में मदद करती है ।
 - **राज्य की सुरक्षा को सुनशिचति करना:** इंटरनेट की संसरशपि सामाजकि स्थरिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लयि महत्त्वपूर्ण है ।
 - इंटरनेट की संसरशपि बड़ी संख्या में अवैध गतिविधियिों और इंटरनेट संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद करते हुए सामाजकि स्थरिता में योगदान देती है ।
 - यह कुछ अवैध संगठनों अथवा लोगों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिको प्रभावति करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकती है ।
 - **झूठी मान्यताओं अथवा अफवाहों के प्रसार पर रोक:** सरकार संसरशपि का उपयोग झूठी मान्यताओं या अफवाहों के प्रसार को रोकने के लयि कर सकती है और इसका उपयोग उनके सार्वजनकि प्रदर्शन आदि जैसी हानकारक गतिविधियिों को रोकने के लयि भी कया जा सकता है ।
 - इंटरनेट की संसरशपि ऑनलाइन उपलब्ध अनुचति जानकारयिों को नयित्तरति करते हुए बच्चों के लयि हानकारक- बाल अश्लीलता, यौन हसिा और अपराध अथवा नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में वसितुत जानकारी प्रदान करने वाले वेबसाइटों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है ।
- **सीमाएँ:**
 - **मोरल पुलसिगि के लयि उपकरण:** प्रमुख सामाजकि मुद्दों पर ध्यान केंद्रति करने के बजाय संसरशपि कानून का व्यावहारकि कार्यानवयन

अन्य लोगों के जीवन को नयितरति करने वाले मोरल पुलसिगि के एक उपकरण में बदल सकता है।

- नए नयिमों के तहत नयिामक संस्थाओं (जो नौकरशाहों से बनी हैं) को प्राप्त व्यापक शक्तियों के राजनीतिक दुरुपयोग का जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।
- **अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता के संवैधानिकि प्रावधान के वरिद्ध:** भारत वविधिताओं वाला देश है है, ऐसे में गहन सेंसरशिपि सभी भारतीय नागरिकों (कुछ उचिति प्रतबिंधों के अधीन) के लयि गारंटीकृत अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता के संवैधानिकि प्रावधान के साथ कई मामलों में संरेखति नहीं है।

आगे की राह

- डजिटिल संचार और सूचनाओं तक पहुँच के लयिटोस वधिकि एवं नयिामक सुरक्षा उपायों के माध्यम से भाषण तथा अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता है।
- AI को पर्याप्त रूप से वनियामति करते हुए इसका उपयोग इंटरनेट की स्वतंत्रता को कम करने के बजाय उसका समर्थन करने के लयि कयिा जाना चाहयि।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/state-of-global-internet-freedom-in-2023>

